जनसत्ता

वक्त का तकाजा

कश्मीर के संदर्भ में चीन के ताजा रुख पर भारत की तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और इससे चीन के साथ-साथ पाकिस्तान को भी समझने की जरूरत है कि किसी भी देश के संप्रभु क्षेत्र की समस्याओं को अनावश्यक विस्तार देने से नई जटिलताएं खड़ी होती हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध कैसे होंगे, इसके बारे में वही दोनों देश तय करेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में गैरजरूरी तरीके से हस्तक्षेप से बचा जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के ताजा भारत दौरे के लिहाज से देखें तो बेजिंग में पाकिस्तान और चीन की बैठक में कश्मीर मुद्दे को लेकर जताई गई चिंता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत अपनी स्थितियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। फिर भी चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक यह खबर आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति ने कश्मीर में स्थिति की निगरानी करने की बात कही और उम्मीद जताई कि 'संबंद्ध पक्ष' शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए मुद्दे का हल कर सकते हैं।

सवाल है कि जब भारत ने दुनिया के सामने यह साफतौर पर कहा है कि अपने संप्रभु क्षेत्र की स्थितियों को वह खुद ठीक कर सकता है और इसमें किसी अन्य की भूमिका नहीं है, उसके बावजूद चीन को इस तरह की बेमानी रुचि दर्शाने की जरूरत क्यों पड़ी! स्वाभाविक ही भारत की ओर से यह कड़ी प्रतिक्रिया आई कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली के रुख से बेजिंग 'अच्छी तरह से अवगत' है और हमारे आंतरिक मामलों पर अन्य देश टिप्पणी न करें। वैश्विक तकाजों के मुताबिक देखें तो एक संप्रभु देश को दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, उसके बाद ही उसे अपने लिए ऐसे रुख की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन कश्मीर के बहाने से पाकिस्तान ने लंबे समय से जिस तरह का रुख अपनाया हुआ है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। यों दुनिया के तमाम देशों को यह जानकारी होगी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इस मामले में किसी तीसरे को अपनी ओर से दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर या दूसरे देशों में मौका मिलते ही पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को विवादित बना कर पेश करने से नहीं चूकता है। उसकी ऐसी ही कोशिशों का नतीजा है कि कई बार कुछ देश कश्मीर के मसले पर भ्रमित हो जाते हैं।

यह संभव है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चीन दौरे में कुछ ऐसी बातें हुई हों, जिसके चलते चीन ने कश्मीर मामले में एक उलझा हुआ रुख सामने रखा। हालांकि पड़ोसी देश होने के नाते उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह भारत की वास्तविकता और तकाजों को समझेगा और उसी के मुताबिक अपनी स्थिति साफ रखेगा। लेकिन विडंबना यह है कि पाकिस्तान से संबंध निभाने के क्रम में अगर वह भारतीय सीमाक्षेत्र की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी करता है तो यह स्थितियों को जटिल ही बनाएगा। भारत ने कश्मीर के संबंध में कोई अहम फैसला किया और वहां के लोगों को इससे आपत्ति नहीं है, तो पाकिस्तान को चिंता जताने की जरूरत आखिर क्यों है? संयुक्त राष्ट्र में या फिर अमेरिका और चीन आदि के सामने इस समस्या को उलझाने की उसकी कोशिश से कोई सकारात्मक नतीजे नहीं अने वाले। फिर चीन की यह कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान से इतर वह भारत के साथ अलग-अलग स्तर पर अपने संबंधों को नया आयाम दे।

अब पलटी

जब से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटा है, कांग्रेस लगातार सरकार का विरोध कर रही है। मगर वह ऊपर से यह भी दिखाने का प्रयास करती रही है कि लोकतंत्र में उसका पूरा भरोसा है। यही वजह है कि जब वहां ब्लाक विकास परिषद यानी बीडीसी के चुनाव की घोषणा हुई तो उसने उसमें हिस्सा लेने का एलान कर दिया। मगर अब उसने इन चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उसका तर्क है कि सरकार लगातार उसके नेताओं को नजरबंदी में रखे हुई है और उन पर तरह-तरह की पाबंदियां लगा कर परेशान कर रही है, इसलिए वह बीडीसी चुनावों का बहिष्कार करेगी। उसका कहना है कि नजरबंदी के चलते उसके नेता चुनाव की अपेक्षित तैयारियां नहीं कर पाए, सरकार ने इरादतन ऐसा किया ताकि उसकी पार्टी चुनाव जीत जाए। गौरतलब है कि जब बीडीसी चुनावों की घोषणा हुई थी, तो कांग्रेस ने पैंथर्स पार्टी के साथ मिल कर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया था। हैरानी की बात है कि तब उसे ऐसा नहीं लगा कि उसके नेता अपेक्षित तैयारी नहीं कर पाए हैं। अगर वास्तव में उसे नजरबंदी पर एतराज था तो वह अपने उस मुद्दे पर अड़ी रहती। यह क्या कि लोकतांत्रिक भी दिखना चाहती है और चुनावों का विरोध भी कर रही है।

जब जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया, तो घाटी में अशांति की आशंका के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया। राजनेताओं के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई। कई विपक्षी नेताओं को उनके घर में ही रखा गया। जब यह स्थिति लंबी खिंचने लगी तो विपक्षी दलों ने शोर मचाना शुरू किया कि इस तरह घाटी के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इससे संबंधित शिकायतें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पहुंचीं। हालांकि उन शिकायतों का कोई उल्लेखनीय असर नहीं हुआ। फिर केंद्र ने स्थितियों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू में ढील देनी शुरू की, विपक्षी नेताओं पर से पाबंदियां हटानी शुरू कर दी। पहले जम्मू संभाग के नेताओं को मुक्त किया गया, फिर कश्मीरी नेताओं पर से कुछ पाबंदियां हटाई गईं, जिसके तहत नेशनल कान्फ्रेंस के नेता आपस में मिल कर विचार-विमर्श भी कर चुके हैं। धीरे-धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। दुकानें खुलने लगी हैं, लोग दफ्तर लौटने लगे हैं, स्कूल खुलने लगे हैं। इस तरह मौलिक अधिकारों के दमन की बात काफी हद तक बेमानी नजर आने लगी है। फिर भी कांग्रेस की चुनावों में हिस्सा न लेने की घोषणा हैरान करने वाली है।

सरकार की नीतियों, उसके फैसलों पर असहमति दर्ज कराना विपक्षी दलों का धर्म है, पर चुनावों में हिस्सा न लेने का उनका फैसला एक तरह से उनके लोकतंत्र में अविश्वास को ही रेखांकित करता है। विशेष दर्जा हटने के बाद यह जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव है। इससे न सिर्फ लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है, बल्कि इससे उनके भरोसे को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। लिहाजा, सभी राजनीतिक दलों से स्वाभाविक अपेक्षा की जाती है कि ऐसे नाजुक मसलों पर एकजुटता जाहिर करें। फिलहाल कश्मीरी लोगों का हौसला बढ़ाने का समय है। इसके लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए। यह तभी संभव है, जब अपने राजनीतिक स्वार्थों को अलग रख कर मुख्यधारा की सभी पार्टियां चुनावों में शिरकत करें। कांग्रेस के ताजा फैसले से उसमें अवरोध ही उत्पन्न होगा।

कल्पमेधा

हमारी रुचि जीवन की कसौटी
है और हमारी इंसानियत
की पहचान।
– रस्किन

क्षेत्रीय विकास की रणनीति

विवेक ओझा

उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के हित में भारत-चीन के नेतृत्व में एनडीबी ने हाल में कुछ बड़े फैसले किए हैं। इस साल अगस्त में बैंक ने डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्रा में कर्ज देने का निर्णय किया है। एनडीबी के अध्यक्ष ने हाल में कहा भी था कि निकट भविष्य में इस बैंक की पचास फीसद परियोजनाओं को पैसा स्थानीय मुद्रा में दिया जाएगा। इससे अमेरिका सहित यूरोपीय देशों के समक्ष यह संदेश जाएगा कि विकासशील देश भी अपने आर्थिक हितों के लिए सक्रिय हैं।

हाल में भारत और ब्रिक्स बैंक, जिसे अब न्यू डवलपमेंट बैंक (एनडीबी) कहते हैं, की संयुक्त कार्यशाला दिल्ली में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एनडीबी से अधिक से अधिक जुड़ाव का अवसर देना था, ताकि विकास के लिए वित्तीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह एक महत्त्वपूर्ण पहल इसलिए मानी जा रही है क्योंकि विकासशील देशों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करना जरूरी हो गया है। इसके कुछ ही समय बाद आंध्र प्रदेश की ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ब्रिक्स बैंक ने चौंसठ करोड़ साठ लाख डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी। इससे राज्य में सड़कों का जाल तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में अपनाए गए आठ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों का आठवां प्रमुख लक्ष्य विकास के लिए वैश्विक साझेदारी था। वर्ष 2002 में मेक्सिको के मोंटेरी में वित्तीय सहयोग बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 2008 में कतर की राजधानी दोहा में और फिर 2015 में इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में भी विकास के लिए वित्तीय सहयोग का वैश्विक आह्वान किया गया था।

जब वर्ष 2015 में सत्रह सतत विकास लक्ष्यों वाला एजेंडा-2030 संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया तो उसमें भी सत्रहवें लक्ष्य के रूप में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी को चुना गया था। ब्रिक्स का न्यू डवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी विकास के लिए इसी वित्तीय सहयोग की अवधारणा पर स्थापित किया गया था और इसी पर काम भी कर रहा है। वास्तव में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर विकास की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आज कई विकास बैंक और वैश्विक आर्थिक संगठन काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं यानी ब्रिक्स देशों में विकास को बढ़ावा देने में एनडीबी की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई है। उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के हित में भारत-चीन के नेतृत्व में एनडीबी ने हाल में कुछ बड़े फैसले किए हैं। इस साल अगस्त में बैंक ने डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्रा में कर्ज देने का निर्णय किया है। एनडीबी के अध्यक्ष ने हाल में कहा भी था कि निकट भविष्य में इस बैंक की पचास फीसद परियोजनाओं को पैसा स्थानीय मुद्रा में दिया जाएगा। इससे अमेरिका सहित यूरोपीय देशों के समक्ष यह संदेश जाएगा कि विकासशील देश भी अपने आर्थिक हितों के लिए सक्रिय हैं। इससे इन देशों की विकसित देशों से सौदेबाजी की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

एनडीबी ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रगति के संवाहक के रूप में वैश्विक पहचान कायम कर ली है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ब्रिक्स को 'ट्रिपल ए' के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रेटिंग दी है। इसके अलावा अगस्त, 2019 में ही एनडीबी ने कहा कि दस फीसद जीडीपी वृद्धि दर के साथ भारत पांच खरब डॉलर अर्थव्यवस्था बन सकता है। एनडीबी की स्थापना के पीछे मकसद विकासशील देशों के लिए बड़ा आर्थिक मंच तैयार करना था। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में ब्रिक्स के चौथे शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने विकास परियोजनाओं और ढांचागत विकास के लिए एनडीबी जैसे बैंक के गठन की संभावना पर विचार किया था। 2013 में डरबन में पांचवें ब्रिक्स सम्मेलन में वित्त मंत्रियों की रिपोर्ट के बाद एनडीबी के गठन पर काम शुरू हुआ और 2014 में ब्राजील में छठे सम्मेलन में इसकी स्थापना के लिए सदस्य देशों ने करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार ब्राजील उद्घोषणा के साथ ही औपचारिक और आधिकारिक स्तर पर इस बैंक के गठन की घोषणा हुई। इस उद्घोषणा में साफ किया गया कि यह वैश्विक स्तर के बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के विकासात्मक कार्यों में सहयोगी और अनुपूरक का काम करेगा। इस प्रकार यह विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं को प्रतिद्वंदी मानने वाला बैंक नहीं है। सात जुलाई, 2015 को रूस में ब्रिक्स के सम्मेलन में एनडीबी एक वैधानिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आ गया था। इसका मुख्यालय चीन के औद्योगिक शहर शंघाई में रखा गया है। आज यह सौ अरब डॉलर पूंजी वाला बैंक हैं।

न्यू डवलपमेंट बैंक एक आज एक अंतराष्ट्रीय

संगठन का रूप ले चुका है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी है। हालांकि इस बैंक की बड़ी विशेषता यह है कि इसका दायरा ब्रिक्स देशों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसके संविधान में दूसरे देशों को सदस्य बनाने का भी रास्ता खुला रखा गया है। इसलिए एनडीबी के आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में साफ कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश एनडीबी के सदस्य बन सकते हैं। बस शर्त यह होगी कि ब्रिक्स देशों की इस बैंक में हिस्सेदारी, मताधिकार के पचपन फीसद से कम किसी भी हाल में नहीं होगी। इस बैंक में सभी पांचों देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की शेयरधारिता और मताधिकार बीस फीसद है। बैंक की चौथी वार्षिक बैठक इस साल एक अप्रैल को केपटाउन में हुई थी। इसमें कहा गया कि बैंक का मुख्य उद्देश्य सतत विकास को और विकास की सतत अवसंरचना को बढ़ावा देना है। इस बैठक में यह ऐलान किया गया था कि क्रय शक्ति समता की दृष्टि से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी वर्ष 2010 के तीस फीसद से बढ़ कर अब छत्तीस फीसद हो गई है। बैठक में एनडीबी की उपलब्धियां बताते हुए कहा गया कि 2017 के अंत तक विविध तेरह परियोजनाओं के लिए 3.4 अरब डॉलर के कर्ज दिए जा चुके हैं। इसके अगले साल यानी 2018 में सत्रह परियोजनाओं को साढ़े चार अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया गया। एनडीबी अब तक कुल तीस विकास परियोजनाओं को कर्ज मंजूर कर चुका है जिसकी रकम आठ अरब डॉलर से ज्यादा बैठती है।

एनडीबी ने जो कर्ज दिए हैं उनमें साठ फीसद कर्ज नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए हैं और इसमें परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा, जल और स्वच्छता प्रबंधन और शहरी विकास को जोड़ दिया जाए तो यह अस्सी फीसद से अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह बैंक सतत विकास और एजेंडा-2030 के हिसाब से सत्रह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सक्रिय हो कर काम कर रहा है। 2018 में इस बैंक को 'एए प्लस' की रेटिंग भी मिल चुकी है। इस रेटिंग से बैंक की पहुंच वैश्विक पूंजी बाज़ार तक अनुकूल शर्तों के साथ हो गई है। सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाते हुए एनडीबी ने 2019 में अपने द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की मात्रा दोगुनी यानी सोलह अरब डॉलर करने की घोषणा भी की है। बैंक ने चीनी इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट से तीन अरब डॉलर मूल्य वाले बांड जारी किए है। बैंक अब दक्षिण अफ्रीका, भारत और रूस में स्थानीय मुद्रा बांड जारी करने की योजना भी बना रहा है। बैंक इक्विटी निवेश भी शुरू करने और परियोजना कोष को कार्यशील बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस तरह के वैश्विक-क्षेत्रीय बैंक आर्तिक संकट से जूझ रहे देशों को मदद के लिहाज से भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। आज दुनिया के ज्यादातर देश मंदी का सामना कर रहे हैं। भारत में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए निवेश और खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में एनडीबी जैसे बैंक विकासशील देशों की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

आस्था और विश्वास

बृजमोहन आचार्य

हमारे देश में असंख्य देवी-देवताओं को पूजा जाता है और इससे जुड़े मेले लगते रहते हैं। एक प्रकार से अपने यहां आध्यात्मिक नदी की धारा निरंतर बहती रहती है। हर उम्र और वर्ग के लोग किसी न किसी श्रद्धा के कारण अपने-अपने इष्ट देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जब परीक्षाओं का दौर आता है तब इसका जोर बच्चों पर भी देखा जाता है। सही है कि परीक्षा के परिणाम में अच्छे अंक हासिल हों, इसलिए विद्यार्थी अपनी काबिलियत के अनुसार मेहनत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चे को उच्च अंक दिलाने के लिए बच्चे की तरह ही परिश्रम करते हैं और उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इन सबके बावजूद कई विद्यार्थियों को यह विश्वास नहीं होता कि वे उच्च अंक से परीक्षा में अपना परचम फहरा सकेंगे। इसके लिए वे अपने तय पाठ्यक्रम के साथ ईश्वर की आराधना भी करते हैं। हालांकि बच्चों को शुरू से ही पूजा-अर्चना और भगवान में विश्वास और श्रद्धा करने के लिए संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता है।

मैं भी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति होने के नाते धार्मिक स्थानों पर जाता रहता हूं। मुझे परीक्षा के दौरान बच्चे को छोड़ने के लिए उसके परीक्षा केंद्र तक जाना पड़ता था। एक दिन बीच रास्ते में मंदिर होने के कारण बच्चा परीक्षा केंद्र जाने से पहले मंदिर की चौखट चूमने के लिए रुक गया था। मैं सोचने को मजबूर हो गया कि मंदिर आदि धार्मिक स्थलों से दूर रह कर केवल मोबाइल और बाइक के बारे में बातचीत करने वाले बच्चे के भीतर अचानक धार्मिक प्रवृत्ति कैसे जागृत हो गई। लेकिन जब मंदिर में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वहां उन बच्चों की भीड़ ज्यादा थी जो सिर्फ परीक्षा के मौसम में ही मंदिर आते हैं। जब मंदिर निकल रहा था तो मेरी नजर दीवार पर गई, जहां अनेक विद्यार्थियों ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास के कारण अपने नाम लिख दिए थे। साथ ही परीक्षा में उतीर्ण करने की गुजारिश भी लिख दी थी।

दुनिया मेरे आगे

अब उन विद्यार्थियों को कौन समझाए कि परीक्षा में साल भर की गई मेहनत काम आती है। लेकिन जब अपनी पढ़ाई और तैयारी पर भरोसा नहीं होता है तो बच्चे किसी चमत्कार की उम्मीद में ऐसा करते हैं। दिलचस्प यह है कि परीक्षा को बहुत सारे एक संकट के तौर पर देखते हैं, इसलिए मंदिरों में विद्यार्थियों के बीच मुझे यह देखने को मिला कि उनमें से ज्यादातर हनुमान के प्रति ही अपेक्षया अधिक श्रद्धा प्रदर्शित कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि 'संकट से हनुमान छुड़ाए, मन, क्रम, वचन ध्यान जो लावै।'

स्कूली जीवन में बच्चों की उम्र इतनी नहीं होती है कि उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाए और वे समय से पहले ही संकट में दब जाएं। इसके अलावा, अभिभावक भी बच्चों को भगवान के प्रति आस्थावान होने की सलाह देते रहते हैं। जब बच्चा परीक्षा देने के लिए घर से रवाना होता है तो उसे गाय को गुड़ खिलाने के लिए दिया जाता है और खुद उन्हें दही और गुड़ खिला कर रवाना किया जाता है, ताकि परीक्षा में प्रश्न-पत्र सही तरीके से हल हो सके। यह सब अंधविश्वास की वजह से किया जाता है, लेकिन अभिभावकों को ऐसा लगता है कि दही खिला कर भेजने से बच्चे का प्रश्न पत्र अच्छा होगा। बच्चे भी जो आमतौर पर अपनी हर बात पर जिद पर अड़ जाते हैं, परीक्षा के मौसम में जिद को छोड़ कर आस्था के भरोसे ही आगे बढ़ने की उम्मीद पाल बैठते हैं।

हालांकि साल भर मेहनत करने और पढ़ाई में व्यस्त रहने वाले विद्यार्थियों को मालूम होता है कि परीक्षा में उनकी पढ़ाई ही काम आएगी, फिर भी 'परीक्षा के खौफ' से भयभीत होने और परिणाम आने के पहले तक वे भगवान की दहलीज पर अपना मत्था टेकने जाते रहते हैं। कई विद्यार्थी व्रत और उपवास करना भी नहीं भूलते है। आस्थावान होना या मंदिर की चौखट पर अपनी हाजिरी देना निजी विश्वास हो सकता है। लेकिन परीक्षा या फिर संकट के समय अपनी मेहनत और बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए। धार्मिक स्थानों पर लोग सद्विचार, सकारात्मक ऊर्जा और समाजसेवा जैसे काम करने की उम्मीद से ही पहुंचते हैं। दूसरी ओर यह भी सही है कि कुछ बाबाओं ने बुरे कर्म करके धार्मिक स्थलों और आश्रमों को शोषण और ठगी का अड्डा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि अब बहुत सारे सोचने-समझने वाले लोगों का ऐसे बाबाओं से भरोसा उठ गया है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि समाज बुरा नहीं होता, उसे राह दिखाने के नाम पर कुछ संत या बाबा कहे जाने वाले लोग कई बार बेईमानी करते हैं। इसलिए जब बच्चा अंगुली पकड़ कर चलना सीख जाए तो उसके बाद उसके भीतर नैतिकता और आस्था के भाव के साथ खुद पर भरोसा करने का भी पाठ पढ़ाया जाए, ताकि परीक्षा पास करने के लिए वह अपने और अपनी पढ़ाई पर विश्वास करे।

लूट की होड़

भारत की आम गरीब जनता पहले से ही यहां मजबूती से अपने पांव जमाए जमाखोरों, सूदखोरों, शिक्षा माफिया-भूमाफिया, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों, तस्करों, चोरों से त्रस्त और परेशान थी। अब जनसुविधा और जनकल्याण के नाम पर जनता को लूटने-खसोटने की कोशिश लगातार चल रही है। मसलन, भारतीय रेलवे के माध्यम से आम जनता से पैसा वसूली ऐसा काम किया जा रहा है, जिसके पीछे उचित तर्क नहीं दिख रहा।

कुछ समय पूर्व भारत सरकार के नीति-निमार्ताओं ने जोर-शोर से यह घोषणा की थी कि हम भारतीय रेलवे में भी विभिन्न एयरलाइंस की तरह फ्लैक्सी या डायनेमिक किराया लागू करेंगे। अब आम गरीब जनता को कैसे इस नई व्यवस्था में लूटा जा रहा है, वह रोज देखने को मिल जाता है। सरकार ने छठ, दीपावली या दशहरे जैसे त्योहारों के मौके पर भारतीय रेलवे की तरफ से खूब प्रचार किया था कि वह आम जनता की सुविधा और सहूलियत के लिए जरूरत भर की 'सुविधा' ट्रेनें चला रही है। इन ट्रेनों में डायनेमिक किराया लागू है। इस त्योहारी मौसम में भारत का कोई गरीब व्यक्ति भी अपनी नौकरी से साल में कम से कम एक बार अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी के साथ त्योहार मनाए। जाहिर है, इस समय कई करोड़ लोग भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। रेल यात्रा का विकल्प भी उनके पास नहीं है।

ट्रेनों के फ्लेक्सी या डायनेमिक किराए में चाल यह है कि जो रेलयात्री अपनी यात्रा तिथि के मुताबिक किसी मजबूरी में जितना नजदीक यात्रा टिकट लेगा, वह उतना ही महंगा होता जाएगा। मसलन जयपुर से सूरत का किराया 5000 रुपए से भी ज्यादा हो जा सकता है! अब प्रश्न है कि सरकार के नीति-नियंता आम जनता को सुविधा दे रहे हैं या लूट रहे हैं! दूसरी तरफ सरकार चुपचाप बड़े पूंजीपतियों के जानबूझ कर बैंकों से लिए कर्ज को न चुकाने पर लाखों करोड़ रुपए आसानी से 'माफ' कर देती है। इसकी क्या सफाई है?

अब सोचने वाली बात है कि वर्तमान में यह कथित लोकतांत्रिक सरकार कितनी लोकतांत्रिक और लोकहितकारी है! कितने दुख और अफसोस की बात है कि भारत की सरकारें यहां के नीति-निर्धारक और कथित अर्थशास्त्री विकसित देशों की नीतियों का अनुसरण करने में देर नहीं करते, जिनकी वजह से आम गरीब भारतीय का और भी शोषण होने लगता है।

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जबकि विकसित देशों में जनकल्याणकारी कार्यों का मतलब वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था निशुल्क है। वहां की सड़कें, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, रेल यातायात की व्यवस्था गुणात्मक रूप से इतनी अच्छी हैं कि वहां का आम आदमी का जीवन बहुत ही सुख और शांति से बीतता है। फिर मन में यह बात बार-बार कौंधती है कि हमारे देश की सरकारें विकसित देशों की इन अच्छी चीजों की नकल क्यों नहीं करतीं?

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

सुकून के लिए

आजकल अखबारों में दिल्ली सरकार के बड़े-बड़े विज्ञापनों में दिल्ली में प्रदूषण कम होने का दावा किया गया है। इसके कारण प्रदूषण की व्यापक समस्या पर फिर से बहस शुरू हो गई है। गौरतलब है कि पिछले चार-पांच सालों से दिल्ली में अक्तूबर-नवंबर माह में दिवाली, पटाखे, पराली, औद्योगिक संयंत्र, वाहनों और निर्माण कार्य के चलते प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का बढ़ता स्तर जानलेवा होता जा रहा है। इस समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान अगली गेहूं की फसल लगाने की जल्दी में धान की खेती के अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं, जिससे उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में प्रदूषण हो जाता है। ये प्रदूषित हवा बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को बहुत नुकसान पहुंचाती है।

हालांकि राष्ट्रीय हरित पंचाट पराली को 2015 में ही प्रतिबंधित कर चुका है, फिर भी पराली जलाने की घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। केंद्र ने भी अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए अलग से कोष बनाया है, जिससे करोड़ों रुपए की सहायता राशि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को जारी की गई है, ताकि किसान को आर्थिक मदद देकर पराली जलाने की बजाय उसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी मदद से निष्पादित किया जा सके।

लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल की ग्लोबल स्टडी बताती है कि भारत में प्रदूषण जनित बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इसमें जीवन प्रत्याशा में कमी से लेकर सांस, मधुमेह, दिल और स्ट्रोक से होने वाली मौतें शामिल हैं। अब समय आ गया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र मिल कर इस प्रदूषण की समस्या से युद्धस्तर पर लोहा लें, ताकि अमूल्य जानें बचें और दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा मिले और वे सुकून की सांस ले सकें।

● *बिजेंद्र कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय*

सहयोग का पर्व

साल में सिर्फ एक बार यह त्योहार आता है, जब पूरा परिवार अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल कर एक साथ हो जाता है। एक दूसरे के लिए उपहार लाना, भरपेट मिठाइयां खाना, घर-घर जाकर मिठाइयां और खुशियां बांटना, रंग-बिरंगी रंगोली बनाना, नए-नए कपड़े खरीदना-बनवाना, घर की पूरी साफ-सफाई करना, परिवार के साथ बैठकर खुशियां बांटना, पुराने किस्से दोहराना, भरपेट मिठाइयां खाना, भाई-बहनों के साथ मिल कर तरह-तरह के खेल खेलना और भगवान को शुक्रिया अदा करना। यही असली मतलब है दीवाली का।

मगर हम इस त्योहार को मनाते हुए लोग दूसरों की जिंदगी क्यों ले लेते हैं? हम जो महंगे-महंगे पटाखे खरीद कर आतिशबाजी करते हैं, वह हमारे वातावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। प्रदूषण वाली हवा को जब हमारे पशु-पक्षी अपने अंदर खींचते हैं, तब वे मरते हैं। इसी जहरीली हवा को जब हम भीतर खींचते हैं तब हमें टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऊपर से जो पैसे हम पटाखों पर खर्च करते हैं, हम उनसे गरीबों के लिए मिठाइयां और कपड़े लाने के काम में ला सकते हैं। ऐसा न करके हम लाखों जीवों की जान बचा सकते हैं, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों की भी मदद कर सकते हैं।

● *मन्नत साहू, गुरुग्राम, हरियाणा*